

प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली

28 अक्टूबर 2021

पॉपुलर फ्रंट ने नागरिकों पर पेगासस के इस्तेमाल की स्वतंत्र जांच के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया स्वागत

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ओ एम ए सलाम ने एक बयान में अनधिकृत निगरानी के लिए पेगासस स्पाइवेयर के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति नियुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

सलाम ने कहा कि भारत के चीफ जस्टिस एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ का यह आदेश मोदी सरकार के निरंकुश रवैये के लिए एक झटका है और यह प्राइवैसी के संवैधानिक अधिकार को बरकरार रखता है। यह आरोप कि सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं, नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और सरकारी एजेंसियों के प्रमुखों सहित 40 से अधिक नागरिकों की जासूसी की गई, भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। यह उन तानाशाही शासनों का एक विशिष्ट व्यवहार है जो नागरिकों और राजनीतिक विरोधियों को असल दुश्मन मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई मौके दिए जाने के बावजूद जवाब देने में केंद्र की झिझक यह साबित करती है कि आरोप में दम है। सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र तकनीकी समिति द्वारा जांच न्याय के हित में एक उचित कदम है। सुप्रीम कोर्ट की यह चेतावनी कि सरकार को हर बार 'राष्ट्रीय सुरक्षा' का छलावा उठाने पर मुफ्त पास नहीं मिल सकता, इससे मोदी सरकार की आंखें खुलनी चाहिए और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता का दायरा तंग करने की कोशिश से बाज आना चाहिए।

डायरेक्टर, मीडिया व जनसंपर्क
मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली